

[श्री मूल अन्व डामा]

Gandak Canal Projects (H.A.H. Dis)

समाप्ति महोदय : प्राप ने भंटी चुनी या नहीं ?

समाप्ति जी, कमेटी ने रेकमेण्डेशन किया वह प्रलग और प्राप का बिल प्रलग, तो प्रब बतलाए कि हम इस को माने या न माने ? प्राप कहेंगे कि यह तुम कैसे कहते हो ? तो हम चुप हैं। प्राप बिल पढ़िये। कौन बाइसचासलर होगा ? पार्लियामेंट में सब से पहले डिस्कशन यह होना है कि बाइसचासलर कौन होना चाहिए। इस में दिया है

The Visitor shall appoint the Vice-Chancellor What will be the qualifications? It will be decided later on

(अध्यक्ष) मैंने कहा एच का तो सवाल ही नहीं है। क्वालीफिकेशन का ता कोई सवाल ही नहीं है।

अब एक एक क्वेश्चन लीजिए। एक तरफ तो प्राप जो ये हिन्दुस्तान के भाग्य विधाता हैं उनके सेनेशन की बात दबिण उन का सेलेक्शन कैसे होगा ? कौन टीचर्स लिए जायेंगे ? हिन्दुस्तान के जिन प्राइमी का कही नीबरी नहीं मिलती वह टीचर बन कर प्राता है और वह फिर सीधे पार्लियामेंट में प्राता चाहता है। पार्लियामेंट में नहीं प्राए ता विदेश जाना चाहता है कारेन कन्ट्रीज के टूर के लिए। जितन कालेज के प्रोफेसर्स बनने हैं वह यह समझने हैं कि किसी न किसी निकडम से कही न बही प्रागे जावे। बाहे कही बाइसचासलर बने या इमैड चले जावे या कही मीटिंग में मेम्बर बने। ट्यूटोरियल या बच्चा का पठाने का ता सवाल ही नहीं है। तो प्रा कीजे इम्पार्टेंट है एच टीचर एच बाइसचासलर, दाना क लिए इमम कुछ नहीं है और प्राब अगर हम कहते हैं कि प्राप ने टेमा क्या किया ता प्राप कहेंगे कि कोई जरूरी नहीं है, हम हरीबली पास कर रहे हैं क्योंकि विजनेम ऐडवाइजरी कमेटी ने कह दिया और लाग कहते हैं कि जल्दी करे, मैं अपना प्रनाव विदग्ना कर। क्यों करू क्योंकि जुलाई में स्थापना करनी है। तो करिए। जुलाई दो महीने हैं, तो दो महीने के अन्दर करिए। . . (अध्यक्ष) . . .

अब मैं जास जास प्वाइंट्स के रहा हू।

श्री मूलअन्व डामा : मैंने तो प्वाइंट कमेटी में प्रेचने का मोशन दिया था। इसलिए मैंने प्राप से प्रार्थना की . . . . .

समाप्ति महोदय : इसीलिए प्राप को प्वाइंट टाइम दिया गया।

श्री मूल अन्व डामा : अब मैं प्रापका प्राबजेक्ट बता रहा हू कि प्राप ने क्या प्राबजेक्ट लिया। सवाल यह पैदा होता है कि जितना पैसा हम खर्च करने जा रहे हैं, उस में लोगों के शारीरिक विकास की भी कोई ब्यबस्था है या नहीं है। जिन बच्चों को प्राप पकायेंगे, उनके शारीरिक विकास के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए कही प्राबीजन किया है—यह प्राप का क्साज 4 है, मुझे तो इसमें कही नजर नहीं प्रा रहा है।

एक बहुत बड़ी बात प्राप ने इस में कही है—

"Any authority of the University may appoint as many Standing or Sub-committees as it may deem fit".

Which is that authority?

समाप्ति महोदय : प्राप अपनी तकरीर बल प्रागे रखे।

17.33 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION

Completion of Western Koel, Rajasthan and Gandak Canal Projects

समाप्ति महोदय : अब हम प्राधा चट्टे की बहल ले रहे हैं। इसमें कुछ बकत मूवर साहब लेंगे, कुछ मिनिस्टर साहब लेंगे। इनके प्रासावा कुछ मवालात भी पूछे जायेंगे। एक बिट्टी भी इस सिलसिले में प्राई थी, लेकिन बकत पर नहीं प्राई, इस लिए उनको इन्कलूड नहीं किया

गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनको भी कुछ टाइन प्रश्न पूछने के लिए बिना जाय।

We divide like this: 10 to 12 minutes for the Mover; then sometime for questions; and then 10 minutes for the Minister to reply.

श्री जोसेफ़ झा (जयनगर) : सभापति जी, भ्रान्तोत्पादन के बृद्धि की बातों को सुनने के बाद यह देश एक बार फिर भ्रान्त सफट के कगार पर खड़ा है, खाद्यान्न महंगे हो रहे हैं, विदेशों से बड़े पैमाने पर मगाने की शर्मनाक तरीके से बातें हो रही हैं। यद्यपि प्रधान मंत्री जी ने इस का खण्डन किया है कि 70 लाख टन भ्रान्त मगाने की बात सही नहीं है लेकिन खाद्य मंत्रालय जिस तरह से मुनाफाखोरो को संरक्षण देने की नीति पर चल रहा है, कुछ महीने के बाद 70 लाख टन या उस का कुछ भाग मगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जो हमारे यहाँ सिंचाई की बड़ी योजनाएँ हैं, खाम कर गण्डक, कोसी, राजस्थान नहर—भ्रान्त सरकार इन्हीं योजनाओं की पूर्ति कर ले तो इतने खाद्यान्न की बृद्धि जरूर हो जायेगी कि विदेशों से मगाने का खतरा खत्म हो जायेगा। लेकिन भ्रान्त तक जो कुछ हम देखते आये हैं—यह सरकार इन योजनाओं को इस दृष्टि से नहीं देख रही है कि हमारी बहुत सी दिक्कतों का हल इन से हो जायेगा। बेकारी के मबाल के लिए, लोगों को काम देने के लिए, क्रेष प्रोग्राम के लिए धनगत-धनगत पैसे सरकार द्वारा दिये जा रहे हैं—हो सकता है कि इन योजनाओं में एक करोड़ लोगों को काम मिल जायेगा, लेकिन यह ममस्या का हल नहीं है। राज्य सरकारें जिन हद तक काबू कर पाती हैं, उस हद तक ध्रान्त पैसा देने के लिए तैयार हैं, फिर भी यदि काम तेजी से पूरा न हो तो उस का ममाधान कैसे होगा। यदि राजस्थान सरकार नहर के काम को नहीं कर पायी है या वह धनगत है तो फिर केन्द्र सरकार को धाने धाना चाहिए, केन्द्र सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि वह स्वयं उस काम को पूरा कराए। ध्रान्त इन योजनाओं के पूरा

न होने से देश का बड़ा प्रहित हो रहा है—यह क्षेत्र सरहद का हिस्सा है, मुर्दा सरहद नहीं है, जिनका सरहद है, बहुत उपजाऊ भूमि है, वहाँ के लोग खतरों का मुकाबला करने में सजग हैं। ऐसी स्थिति में यदि राजस्थान सरकार उस के लिए कम उत्सुक है तो भारत सरकार को सचेष्ट हो कर धाने धाना चाहिए और उसे पूरा कराना चाहिए। ध्रान्त हम के लिए ध्रान्तारिटी बनाये और रकम दे कर, उन को ध्रान्तिकार दे कर इस पाच साला योजना के ध्रान्त-ध्रान्त इन तीनों योजनाओं को पूरा कराये।

हमारे मंत्री महोदय से जब प्रश्न का जबाब पूछा जाता है तो बड़ी सदिच्छा के रूप में नीति का गैलान कर देते हैं। लेकिन जब उन से स्पष्ट जवाब देने के लिए कहा जाता है तो उस समय उल्टा जवाब दे देते हैं। जिस प्रश्न पर ध्रान्त की बहम शुरू हुई है, उस का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा था—

“Efforts should however be made to complete the Western Kosi Canal, Rajasthan Canal and Gandak canal during the Fifth Plan”.

यह उन का लिखित जवाब था लेकिन जब बाद में स्पष्टीकरण की मांग की गई तो उन के जवाब में मालूम पड़ता है कि वह उन में मुकर गये। जब उन से पूछा गया कि 5म पंचवर्षीय योजना में पूर्ण होगी या नहीं तो कहने लगे कि राज्यों से जराब आयेगा तब विचार करेंगे।

सभापति जी, इन में कुछ योजनाएँ तो राजनीतिक हथकण्डों के रूप में इन्फेमाल की जा रही हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि पश्चिमी कोसी नहर का तीन बार उद्घाटन हुआ लेकिन कार्य ध्रान्त तक ध्रान्त नहीं हुआ। देश में ऐसी कोई भी दूसरी योजना नहीं है जिस का तीव्र बार उद्घाटन हुआ हो। एक बार भी जगजीवन राम जी ने 1957 में उद्घाटन किया था, जब वह देल मंत्री थे। उस के बाद 1962 में जब श्री विनोदानन्दजी मुख्य मंत्री थे, मतदान में 15 दिन पहले उन्होंने उद्घाटन किया और

[श्री भोगेन्द्र झा]

तीनरी बार श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने उदघाटन किया . . . . .

सभापति महोदय : उसी जगह पर ?

श्री भोगेन्द्र झा : ठीक उसी जगह पर—पश्चिमी कोसी नहर पर और यादगार के तीन स्तम्भ खड़े किये गये और आज वे तीनों स्तम्भ रो रहे हैं।

चौथी बार फिर उदघाटन करने की योजना थी और सुना था कि प्रधान मंत्री जी जायेंगी, लेकिन फिर हम ने कहा कि हम विरोध करेंगे अगर वह उदघाटन के लिए आयेंगी। कहने का तात्पर्य है कि तीन बार उदघाटन हो चुका लेकिन आज तक कार्य आरम्भ नहीं हुआ, एक इंच जमीन भी बहा नहीं ली गई और खुदायी की तो कोई बात ही नहीं है। हर चुनाव के पहले उम का इन्तेमाल करो—गेमी शासक दल की नीति रही है। जब भी कार्य आरम्भ करने की बात आती है—उम दिन, सभापति जी, मैं यह सवाल उठाया था—बच्चा बड़े बड़े भूम्यामियों का एक तबका हम में स्थापित हो रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ—बिहार सरकार के जो बड़े बड़े भूम्यामी हैं, जो मिनिस्टर भी हैं, हजारों एकड़ जमीन के मालिक हैं हदबन्दी कानून से बचन व लिए, चोरी करने व लिए ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि यह योजना पूरी ही न हो और मैं जानता हूँ जब तक जन-आन्दोलन उन के गले पर सवार नहीं होगा तब तक मैं पकड़ से नहीं आयेगा। गेमें लागू मिनिस्टर बने हुए हैं और इन लोगों ने सवणा की है कि अगर यह नहर चालू हो गई तो उन की आधी जमीन हदबन्दी से चली जायेगी, इस लिए छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं के जरिये वे लोगों पर अहसान डालना चाहते हैं। एक बार हम गांव में दे दिया, तो दूसरी बार दूसरे गांव में दे दिया अगर यह योजना पूरी हो जायेगी तो अहसान डालने का मौका नहीं रहेगा, सब के लिए सिंचाई का प्रबन्ध हो जायेगा। उस दिन योजना मंत्री जी ने इस बात का खण्डन किया था, लेकिन महाराष्ट्र में भी यही हुआ है। महाराष्ट्र के सिंचाई

मंत्री जी ने भी ठीक यही काम किया है और अब तो वह सचका 'फिफ्ट' सप्ताहिक में भी छप चुका है। 4 अप्रैल को यह प्रश्न यहां आया था, उस के बाद उस में उठा—वहां की ऐंसा ही हुआ है।

पश्चिमी कोसी नहर के बारे में एक बहाना यह किया जाता है कि नेपाल ने भूमि नहीं दी है। लेकिन अब तो नेपाल ने भी भूमि दे दी है, वहां तो खुदायी भी शुरू हो गई है, लेकिन भारत के हिस्से में आपने कुछ नहीं किया है और न एक इंच जमीन अभी तक अधिग्रहण की गई है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

जहां तक राज्य सरकारों की मांग का सवाल है, मेरे प्रश्न के उत्तर में सिंचाई मंत्री जी ने कहा है कि पश्चिमी कोसी नहर के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 25 करोड़ रुपये की मांग की गई है। पूरी परियोजना 40 करोड़ की है। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार की जो भी मांग है उसका केन्द्रीय सरकार पूरा मान लेता किफयत प्लान में उसको पूरा करने का सवाल ही नहीं है किस्म प्लान में ले जाने की बात निश्चित रूप से होगी। सी फीसदी भी मान लिया जाये तब यह स्थिति होगी क्योंकि केवल 25 करोड़ की मांग की गई है। वह और रुपया मंगते हैं, अलग-अलग ऐसी योजनाएं हैं जो लागू हो तो पैसा बचेगा क्योंकि दो फिट की खुदायी हुयी और 8 फिट की नपायी हुई, ऐसे ठेकेदार बड़ा पर बैठे हुए हैं जोकि शासक दल को बोट देने वाले हैं लेकिन ऐंसा नहर की योजना जा टिकाऊ होगी उसकी दिवचस्पी की स्थिति यह है कि 25 करोड़ की मांग की है जबकि 40 करोड़ में कम खर्चा नहीं होगा। बड़ी राजस्थान का मामला है। इनमें बड़े पैमाने पर बेकारी है, मैं प्रोद्योग की बात कही गई है, वर्तमान योजना मंत्री ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है लेकिन अगर राजस्थान, मध्य, पश्चिम कोसी नहर का काम प्रायः बुद्धि पर चालू कर दे तो उससे बड़े पैमाने पर उन इलाकों के लिए ही कही, अमल-

बगन के इलाकों में भी बेकारों को काम देने का तुरन्त और कोई साधन हो नहीं सकता है और अधिकार का इन्तकाम तो उससे होगा ही। फिर कौश प्रोग्राम के लिए अलग से वैसे की मांग क्यों कर रहे हैं। राज्य सरकारें अन्न मागती हैं तो उसके लिए हमें अमरीका से धतूरा मगाना पड़ रहा है। अगर फ़्लोरिडन साहब इस विभाग के मन्त्री रहते तो 70 लाख टन जबर धतूरा मगायेंगे और प्रधान मंत्री का गलत माहित करेंगे इस बात का हमें इत्मीनान है। अन्न मन्त्रालय मुनाफ़ाखोरो को बचाने के लिए चल रहा है। मैं कीमत तय करने वाली कमेटी से था और इनके रुख का देखकर मैं यह कह रहा हूँ। ऐसी स्थिति में यह जो बड़ी योजनाएँ हैं उनको केन्द्र निश्चित रूप से पूरा करे, राज्य के अगिये कगण, खुद करे या फिर बेहतर हागा कोई स्वतन्त्र प्राटानामम एगारिटी कायम कर दे लेकिन पैसा निश्चित रूप से दे, पाचवी योजना के अन्त तक निश्चित रूप से पूर्ण करने की गारन्टी करे ताकि खाद्यान्न की जा कमी है उसको पूरा करने का दिशा में देश भागे बढ सकें। इस आग्रह के साथ मैं मन्त्री जी क, बयान चाहता हूँ क्याकि हमने हमारे देश की उन्नति का सम्बन्ध है हमारे देश की आजादी और प्रभुसत्ता का इससे सम्बन्ध है, हम जानते हैं भूख मरेगे ता धतूरे के लिए अमरीका दोहन पड़ेगा और जा हमारी प्रभुसत्ता पर अमरीका से चोट पड़ रही है वह खतरा बढ जायेगा। पी० एल०—490 की बात हमारे सामने आयेगी। इस आग्रह के साथ मैं चाहता हूँ मंत्री महाशय गान जवाब न दे, स्पष्ट जवाब दे कि इन तीन योजनाओं को चौकी योजना में निश्चित रूप से पूरा करेंगे, सारा पैसा उपलब्ध करायेंगे, राज्य सरकार भागे या न भागे क्योंकि जिनका खर्चा हमारा उमका हिसाब रखा है। और आप एक डेडेन्डेंट एगारिटी कायम करेंगे, केन्द्र का सुपरविजन बहा रहेगा और इस तरह से आप इनको पूरा करके रहेंगे। इस आग्रह के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

श्री भूखण्ड अना (पाली) : सभापति जी,

राजस्थान के लिए राजस्थान कैनाल एक बरदान है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप स कैनाल को अगली पंचवर्षीय योजना में पूरा कर देने या उसने भी कोई और हकाबट पैदा होनी और हम केवल एक स्वयं देखते रहेंगे कि वह कब पूरी होती है।

हमारे अभी जो मवाल हमारे सामने है क्या पोग डैम के सम्बन्ध में आपको कैबिनेट का निर्णय मान्य है कि सारी पाचो टनेल बन्द होनी चाहिए, क्योंकि उससे जा पानी मिलेगा वह राजस्थान में 12 महीने कैनाल में पानी बहेगा लेकिन ऐमा निर्णय होने के बाद भी उसका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हुआ जिसकी वजह से हमको पानी मिलेगा नहीं, हम खेती करने से महकम हो जायेंगे। 10 लाख एकड़ जमीन मिचित नहीं हो पायेंगी। तो जा निर्णय लिया गया था क्या उसके पीछे आप जा रहे हैं यह मवाल है।

तीसरे मैं जानना चाहता हूँ कि शुभ्रघात में राजस्थान कैनाल की कुल किनने धन राशि की योजना थी और आज उसका पूरा करने में कितना पैसा लगेगा और क्या उतनी धनराशि आप अगली योजना में उपलब्ध करेंगे और उस काम को पूरा करावेंगे—यह बतायें।

श्री रामाक्षतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, पश्चिम कासी राजस्थान और गण्डक नहर योजनाओं का केन्द्रीय सरकार के हाथ में लेने की माग बार-बार म मदन में उठाई गई है तो इस सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार इस मुद्दा का मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है। मैं सके सामने कौन सी कठिनाइयाँ हैं जिनकी वजह से वह ऐमा नहीं कर सकती है? अगर मचमूच में सरकार ऐसा कर ले तो हमारे देश के बहुत बड़े हिस्से में जा अनाज की कमी है वह पूरी हो सकती है। तो केन्द्रीय सरकार को उन्हें अपने हाथ में लेने में कौन सी कठिनाई है?

**श्री विष्णुसि सिन्हा (कोसीहारी) :** सभापति जी, गण्डक योजना जिसमें 35 लाख एकड़ की सिंचाई होगी, नेपाल से इसका सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश से सम्बन्ध है, बिहार से सम्बन्ध है, तीन स्टेट्स से सम्बन्ध है और इसमें अब तक 1 अरब 30 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और इनके हिसाब से केवल 3 लाख एकड़ में सिंचाई हुई है। आप कह सकते हैं इतना रुपया कहाँ तक दें, उससे इन्फ्लेशन होगा और वह बात हम समझ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि नेपाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से इसका सम्बन्ध है और इसका एग्जीक्यूशन केवल नेपाल में होता है और हमारी तरफ में यू०पी० गवर्नमेंट कुछ करती है लेकिन कंसालिडेटेड काम नहीं होता है। अगर इसके निर्माण की जल्दी से व्यवस्था की जाये तो 35 लाख एकड़ में सिंचाई करने में मारे देश में फूड प्रॉब्लम बहुत हद तक हल हो सकती है। पता नहीं केन्द्रीय सरकार क्यों अपने हाथ में इसको नहीं लेती है जबकि कटरापागा गुजरात में है और बंगाल की योजना का नाम में भूल रहा है—यह दा स्कीमे सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने बना के उन स्टेट्स को दे दी। एक बार फब्रुअरी माह जब इसके मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि इसको सेन्ट्रल गवर्नमेंट ले लेगी लेकिन आप जानते हैं हमारे आपस में राजनीति चलती है, मोरारजी भाई ने कहा कि नहीं लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ धर माहब बहा चल्कर देखें, वे प्लानिंग के सुयोग्य मंत्री हैं। मैं कहना हूँ कि जल्दी से जल्दी हिन्दुस्तान की फूड प्रॉब्लम मालव होंगी अगर गण्डक योजना को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले ले और लेकर जल्दी से जल्दी बना दे। अगर केन्द्रीय सरकार इसको नहीं बनाती है तो यह बहुत दिनों तक चलती रहेगी, 12 साल तो हो गये और अभी नहीं मालूम और कितने साल लग जायेंगे तथा जितना पैसा लगना है उमका गिटने निकलता नहीं है।

**श्री जगन्नाथ सिन्हा (मधुबनी) :** पश्चिम कोसी नहर एक बहुत बड़ी योजना है, इसकी स्वीकृति में ही बहुत टाक मटोल हुयी। अब जब स्वीकृति

हो गयी है तो कार्यान्वयन में टाक मटोल की नीति का सहारा लिया जा रहा है। केवल नेपाल की सीमा में काम प्रारम्भ हुआ है और वहाँ भी काम के मार्ग में अनेक बाधाएँ हो रही हैं, या उपस्थित की जा रही हैं यह स्पष्ट नहीं है और हिन्दुस्तान की सीमा में इसकी चर्चा भी नहीं है। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूँ भारत की सीमा में कब से काम होने जा रहा है।

दूसरे इस काम को केन्द्रीय सरकार के द्वारा कराये जाने के मार्ग में क्या कठिनाइयाँ हैं ?

तीसरी बात यह है कि बिहार सरकार ने लिखित रूप में अपनी प्रसमर्थता व्यक्त की है और केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया है कि यह कार्य केन्द्रीय सरकार के द्वारा ही हो और यहाँ बिहार के जितने एम० पी० हैं, किसी भी पार्टी के, उन सबों का यह आग्रह है तो मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करूँगा कि वे इसकी स्वीकृति दे जिससे यह काम ठीक और उचित समय पर हो सके।

**श्री लालजी भाई (उदयपुर) :** पूरा राजस्थान प्रकाल से पीड़ित रहता है, और इस समय भी है, मैं जानना चाहता हूँ कि राजस्थान नहर कब तक पूरी हो जायेगी जिस से हम लोगों को राहत मिले, और वहाँ पर कितनी धनराशि खर्च होगी तथा कौन सी प्रबन्धन कब तक पूर्ण हो पायेगी। यह मैं जानना चाहता हूँ।

**THE MINISTER OF PLANNING (SHRI D. P. DHAR):** Sir, I fully share the concern and the anxiety of hon. Members with regard to the progress of these three important projects, and I also share their wish that the Central Government and the State Governments in concert should do their best to accelerate the completion of these projects for the common good of the country and essentially for increasing food production. While this objective is unexceptionable, some of the difficulties, if I may say so with your permission, may kindly be borne in mind.

As far as Kosi is concerned, it is not one project. It, in a sense, consists or comprises of two projects—the Kosi Canal and the Western Canal. An hon. Member has just asked me a question as to whether we have been able to clear that part of the Western Kosi project with Nepal which concerned that country. This in itself is an explanation of the delay that has been caused in this particular part of the Canal. It is only last year that we have come to an understanding with His Majesty's Government of Nepal with regard to the acquisition of the required land, over 34 km in Nepal territory. We have acquired land to the extent of 33 km. so far, not a bad job in a year. and work within the Nepalese territory is proceeding full speed ahead. Unless and until we are able to complete the headworks for this Canal which will lie in the Nepalese territory, it would not be feasible to proceed on an extensive basis with the work of the extension of this Canal within Bihar.

I am grateful to the hon. Member for having made some archaeological studies about the various stones and foundations which have been laid for the Canal. I would have been grateful, at the same time, if he had kindly cared to take into account some of the difficulties which were inherent in this project.

**SHRI BHOGENDRA JHA:** I do not agree that the Government of Nepal was to blame in this case. I have stated in this House earlier that the delay was on our side.

**SHRI D. P. DHAR:** I am sorry, Sir, that it was not an invitation to the hon. Member to blame an independent, sovereign country, Nepal. It is always our luck, or ill luck, to invite all the criticism and blame on ourselves. Therefore, the hon. Member need not use his knowledge to instruct me as to the causes of the delay for this Canal. I was only submitting some facts which were raised about which some enquiry was made by my hon. friend here

As far as the Gandak Canal is concerned, I would submit that this is one of the finest projects we have conceived in our country. It is capable of irrigating in its final phase nearly 1,100 thousand odd hectares of land in Bihar. The picture which Shri Bibhuti Mishra has drawn about the slow pace of the development of this Canal, more or less, corresponds to facts. These facts are unfortunate and these facts deserve to be remedied quickly. What steps we propose to take in that regard I will presently come to them.

The Rajasthan Canal, like Kosi Canal, is also a two-stage project. It is not in that respect one project. It is a two-stage project though it carries the same label, the same name, namely, the Rajasthan Canal. We have to, therefore, deal more effectively, more expeditiously, with the second stage of this project.

Before I proceed to answer one by one the questions which have been raised regarding the financial outlays in the Fifth Plan, regarding the provision of autonomous boards in regard to ensuring the technical and administrative guarantees for the completion of projects, before I come to detailed examination of these questions, I would submit for the information of the hon. Members that, in the first instance, the Fifth Plan is yet to be prepared. It would be slightly irresponsible of me if I anticipate in exact terms the quantum of money that will be available for these projects. I can make a broad guess and I am prepared to share that guess with the hon. Members. I hope, the hon. Member from Bihar Shri Bhogendra Jha, will not later on hold me to having indulged in a speculative exercise which I am doing purely for his satisfaction.

**SHRI BHOGENDRA JHA:** Only for implementation.

**SHRI D. P. DHAR:** My greater satisfaction will be to satisfy him by implementing these projects. If the implemen-

[Shri D. P. Dhar]

tation of these projects does not satisfy the hon. Member, I do not know what else will do.

In any case. I would submit, as far as Kosi and Gandak projects are concerned, I feel fairly confident that, by and large, appropriate financial outlays will be available for the Kosi Project and fairly appropriate outlays will be available for Western Kosi Canal in Bihar. I feel equally confident about the Gandak Project. About the Rajasthan Canal, Stage I, I am equally confident that the required amount will be available in the Fifth Plan period. We have only to examine the question of making the necessary financial outlays possible for the Rajasthan Canal, Stage II. This amount, according to our estimates, will be of the order of Rs. 89.12 crores. So far, in the Fourth Plan, it is our estimate that not more than Rs. 2-1/2 crores to Rs. 3 crores will be spent on this. Therefore, I am not sure that the entire balance amount of Rs. 86 crores will be available for the completion, in all respects, of the Rajasthan Canal, Stage II at this point of time. But taking into account the importance of this Canal, taking into account the benefits which are likely to accrue from this Canal and also, taking into account the fact that the Canal passes through one of the most arid and one of the most dry zones of our country, I think, the Planning Commission will do its utmost to see that this Canal is not stalled for want of finance and we will do our utmost to ensure its completion in the Fifth Plan period. Here it has been suggested that we should have autonomous boards. I would submit for my very learned and knowledgeable friend, Mr. Jha, the fact that there are boards at present which are functioning. For example, for Gandak, there is a Board under the chairmanship of the Governor of Bihar. For Kosi, there is a Board functioning under the chairmanship of the Chief Minister. Of course, it has been unfortunate that, for some years, we have had a spate of Chief Ministers in Bihar. That has somewhat

disturbed the continuity of the process of development.....

18 hrs.

SHRI BHOGENDRA JHA: Did the Chief Ministers know of this fact that they were the Chairman of the Board? At least does the present Chief Minister know that?

SHRI D. P. DHAR: Mr. Jha's Party was a party to these frequent changes. I mention this merely to draw on the knowledgeability of facts which Mr. Jha claims with regard to this particular project.

As far as Rajasthan Canal is concerned, there is a Committee of Directors under the chairmanship of the Central Minister for Irrigation and Power and the Chief Minister happens to be a member.....

SHRI BHOGENDRA JHA: Are these autonomous Boards?

SHRI D. P. DHAR: I am slow in explaining my facts. I would be very grateful if the hon. Member could bear with me. Perhaps he might find some satisfaction in the submissions I am about to make.

I have said that it is not a fact that there are no Boards, that there are no directive authorities, that there are no organisations which are in charge of these projects. There are Boards. But what is the difficulty? The difficulty is that these Boards have so far, as the Estimates Committee have at one stage pointed out, concentrated on the completion of the engineering part of the project. The concurrent need to develop the areas with the help of the potential created by these projects has not been either felt or appropriately satisfied. Therefore, we have come to the conclusion, along with the hon. Member, that what we need is a different type of organisation, an organisation which is multi-disciplined in character, which has various disciplines connected with agricultural production in its composition. And when we talk of such a Board, when we talk of autonomy—I think it is a much-abused word, at any rate an ever-used word—, when we talk of a Board

which is multi-disciplined in character, we also want that it should be invested with sufficient powers more or less of the Government of the State, to deal with the problems as they arise and to deal with all the questions which are related to the speedy execution of the project. For this, we are in correspondence with the States, and I have been assured by all the three States concerned—by Uttar Pradesh, Bihar and Rajasthan—that Boards of this character would be set up.....

**SHRI BHOGENDRA JHA:** By what time?

**SHRI D. P. DHAR:** Fairly soon.

The third question is whether the Centre would take over these—this was what was said before and what has been asked once again.

I need not remind hon Members that...

**श्री लालजी झाई :** हर योजना के लिये एक प्रबंध रखी जाती है। राजस्थान नहर के लिए क्या प्रबंध रखी गई है ?

**SHRI D. P. DHAR:** Irrigation is a State subject. Therefore, it is not enough declaring a wish that such and such project should be taken over by the Centre or it can automatically take it over etc.

**श्री बिभूति मिश्र :** मभापति महोदय

**SHRI D. P. DHAR:** I am prepared to answer a supplementary question.

**श्री बिभूति मिश्र :** मभापति महोदय, गण्डक का सम्बन्ध नेपाल से है। प्राचा बैराज नेपाल से पड़ता है और प्राचा हिन्दुस्तान में पड़ना है। अगर गण्डक योजना को मेट्ट ले ले तो नेपाल से प्रवाह और डीलिंग में महुलियत होगी। प्राच स्थिति यह है कि बिहार गवर्नमेंट यहां चिट्ठी लिखती है और वह यहां से नेपाल जाती है और नेपाल से यहां जवाब आता है

और वह बिहार गवर्नमेंट का भेजा जाता है। यद्यपि इरिगेशन एक स्टेट सबजेक्ट लेकिन प्राचा रूप्या सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता है, इस लिए वह इन योजना को ले ले।

**श्री रामाक्षतार शास्त्री :** क्या मंत्री महोदय न इन सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों से सलाह-सम्बन्ध किया है ? अभी क्या चलेंगा कि वे लोग इन के लिए तैयार है या नहीं और इन से क्या कठिनाई है।

**श्री डी०पी० धर :** प्रानरेबल मेम्बर और श्री मिश्र की क्वाहिश का मुझे इज्जत है, लेकिन उस को पूरा करने के नरीके होने है और वे नरीके ऐसे नहीं हो सकत, जो प्राईन के बिनाफ हो। प्राईन में यह बात माफ है कि सिचाई का सबजेक्ट स्टेट्स के प्रन्प्यार में है। अगर वह सबजेक्ट हम ने उन में हासिल करना है, या उस सबजेक्ट पर नेजिमेंट करना है, या उस के सिलमिने में किमी नरीके से बराहे-गाम्न काम करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि कुछ प्राईनी कदम उठाये जाये। मैं कहा है कि मुझे प्रानरेबल मेम्बरों की इन क्वाहिश का एह-तराम है, लेकिन एहतगम काफी नहीं है। एहतगम के सामने प्राईन की कुछ क्वाबटो हैं और उन क्वाबटो को हम ने दूर करना है। साफ और दियानतदानी की बात यह है कि जहा तक मेरा ताल्लुक है, मैं अभी इस नतीजे पर नहीं पहुचा हू कि हमारी गियामती सरकारे इस काबिल नहीं है कि वे इन प्राजेक्ट्स को मुकम्मल कर सके। लेकिन जब मेरे मोहतरिम दोस्त और इन ऐवान के मेम्बर यह समझते हैं कि इन प्राजेक्ट्स में ताखीर हो रही है, इस में बहुत बकन लग रहा है, इस लिए सरकारकी हुकूमत को इन्हे अपने हाथ में ले लेना चाहिए, तो मैं उन से अर्ज करूंगा कि अगर ऐसे हालात हमारे सामने प्राये और इम इम बात पर मुतम-ईन हुए कि इन प्राजेक्ट्स की तकमीम स्टेट सरकारा के बम का गंग नहीं है, तो जाहिर है कि ऐसे बड़े प्राजेक्ट्स के मुनासलिक सरकारकी



[श्री डी० पी० धर]

सरकार कुछ न कुछ मुनासिब कदम बन्दर उठावेगी।

श्री जगन्नाथ मिश्र : बिहार सरकार ने यह रिक्वेस्ट की है कि बंस्टन कोसी कैनल का एकसीक्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले।

श्री डी० पी० धर : वह रिक्वेस्ट धाते धाते बन्द लगता है। अभी वह हमारे पास नहीं पहुँची है। मुझे धानरेबल मेम्बरों की बकालत पर सुबहा नहीं है, लेकिन अगर कोई खत-यत्न उन की तरफ से आए, तो भ्रच्छा हो।

श्री भोलेन्द्र झा : वे ध्राप के पास रिक्वेस्ट नहीं भेजेने।

श्री डी० पी० धर : यह फैसला ध्रापस में कर लीजिए। अगर ध्राप मुझ पर णनवार करते हैं, तो मुझ पर छोड़ दीजिए।

जहा तक इन तीनों प्रोजेक्टम का ताल्लुक है, झा साहब ने कई बातों का तजकिएग किया है। जाहिर है कि कोसी, गडक और राजस्थान कैनल में से कुछ न कुछ सिमासत निबालना मकसूद होना है। उन्होंने कुछ निगामत इम में झाड दी— कुछ धपूरे की और कुछ इमरी बाता की। लेकिन मैं उन बातों में उलझना नहीं चाहता। क्योंकि उन बातों का कोई खास ताल्लुक हमारी बहम के साथ नहीं है। इसलिए मैं ध्राप की खिदमत में मिर्फ यह भ्रजं करना चाहता हू कि ये तीन प्रोजेक्टम और यही तीन प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि सारे देश में हम न कोई बीम एक प्रोजेक्ट्स

ऐसे चुन लिये हैं जिन को हम नेकनल प्रोजेक्ट कहते हैं। नेकनल प्रोजेक्ट इस बजह से कहते हैं कि कौमी हैसियत में उन की एक खास गहमियत है और उन प्रोजेक्ट्स में इस तरह के फवायब हासिल करने की गुवाइशें हैं जिससे कि हमारे भनाज की जो पैदावार है उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और गडक, कोसी और राजस्थान इस सिलसिले में एक इम्तियाजी हिस्ता रखते हैं। इस सिलसिले में इन तीस प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि सारे हिन्दुस्तान में फैले हुए है चाहे वह वेस्ट बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे उड़ीसा हो और चाहे हमारे दक्षिण के राज्य हो, वहा भी इस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, और हमने इसीलिए इम बात का फैसला किया है कि मौजूदा प्लान में, चौसे पच वर्षों प्लान के आखीरी साल में जो, कि धब चल रहा है, हम इन पर ऐडवांस गैरान लेने की बान मांच रहे है। उसके लिए, पैसा भी रखा गया है बजट में। ध्राप इत्मीनान रखिए कि हम पूरी कोशिश करेगे और हम को पूरी कोशिश करनी चाहिए। इम में मैं ममझता हू कि झा साहब जरूर टम से गिले व शिकायते करे लेकिन धब काम करने का वक्त ध्राया है और उममें वह हमारी मदद करे। हम ध्राप के मसकूर है।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

18.12 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, May 8 1973/Vaisakha 18 1895 (Saka).*